

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा०उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 18 फरवरी, 2009

विषय- जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर में स्थापित सिविल जज (जू.डि.) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-26/XXXVI (2)/08-1-सात (बी)/02, दिनांक 28 जनवरी 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर में स्थापित सिविल जज (जू.डि.) के अस्थाई न्यायालय के लिए स्वीकृत सभी अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 01.03.2009 से 28.02.2010 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या-11-सात-(बी)/छत्तीस (1)न्याय अनु०/2004, दिनांक 16.10.2004 द्वारा किया गया था।

2- उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक '2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-सिविल और सेशन न्यायाधीश-00' की सुसंगत प्रारम्भिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए०-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपटित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24 (8)/92, दिनांक 7.11.92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त), द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अर्न्तगत प्रसारित किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव।

संख्या 23 (1)/XXXVI(2)/2009-1-सात (बी)-02-तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2- जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 3- सिविल जज (जू.डि.) लक्सर, हरिद्वार।
- 4- वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(क०पी०पाटनी)
अनु सचिव।